(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन योजनाओं का पूरा लाभ अल्पसंख्यक तक पहुंचे ?

**□वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) :** (क) से (ग) : आठवीं योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ 1992-93 के दौरान आय के मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यकों और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की एक स्कीम मंजूर की गई थी, ताकि वे विभिन्न प्रतियोगिता/प्रवेश परीक्षाओं में समानता के आधार पर भाग ले सकें । यह स्कीम राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है ।

दो अन्य स्कीमें यथा, "आधुनिक मदरसा शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता" और "शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र सघन कार्यक्रम" भी चला रहे हैं । पहली के अन्तर्गत मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की स्कीम बनाई गई है, ताकि विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, आधुनिक भारतीय भाषाओं, हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन आरंभ करने के लिए मदरसा और मकतब जैसी परम्परागत संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा सके । इस स्कीम के लिए आठवीं योजना में एक करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित किया गया है । शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र सघन कार्यक्रम की स्कीम राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों, जिन्हें इस समय चल रहे कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया है, के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है । इस स्कीम के लिए आठवीं योजना में 16.27 करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित किया गया है इसके अलावा, कार्रवाई के कार्यक्रम द्वारा चिह्नित सभी 41 अल्पसंख्यक सघन जिलों में 15 सूत्री कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक पोलिटेक्निक बनाए गए हैं ।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की स्थापना करने की घोषणा की थी ।

(घ) स्कीमों के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित विभागों द्वारा इनका अनुरीक्षण किया जा रहा है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और सलाहकार समितियों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की स्कीम की देख-रेख, अनुरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है । प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए निर्धारित समय अनुसूची का कठोर अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि स्कीमों के लाभ इन लाभ-ग्राहियों को मिल सकें ।

**आयकर विभाग में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति**

2583. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में राजकोट में आयकर आयुक्त द्वारा विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें से कुछ विकलांग उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार 30 नवम्बर, 1990 तक नियुक्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयकर उपयुक्त द्वारा एक प्रतीक्षा-सूची तैयार की गयी थी और प्रतीक्षासूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम क्या-क्या हैं, और

(च) प्रतीक्षा-सूची के उम्मीदवारों की कब तक नियुक्ति किए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

**□वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :** (क) जी, हां

(ख) आयकर आयुक्त, राजकोट ने, रोजगार कार्यालय से प्राप्त नामों में से चपरासियों के पद

के लिए 24 उम्मीदवारों की एक योग्यता-क्रम-सूची तैयार की थी । इस सूची में शारीरिक रूप से विकलांग तीन प्रत्याशी भी शामिल थे।

(ग) और (घ) : शारीरिक रूप से विकलांग एक प्रत्याशी की नियुक्ति कर दी गयी है ।

(ङ) 13 उम्मीदवारों की एक प्रतीक्षा सूची बनायी गयी है जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग दो उम्मीदवार अर्थात् सर्वश्री भाठी दिलीप सिंह बहादुर सिंह और मारू सरोजबाला जसवंत राय शामिल है ।

(च) संगत-समय पर रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण, प्रतीक्षा-सूची में से किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जा सकी, परन्तु योग्यता और नियमों के अनुसार 31-3-94 तक उनकी नियुक्ति कर दिए जाने की आशा है ।

**INCREASE IN WHOLE SALE PRICES**

2584. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an increase in the wholesale prices is immediately reflected at retail level;

(b) whether it is also a fact that there is much delay in the fall of wholesale prices to reflect at retail level;

(c) if so, the reasons thereof ; and

(d) whether Government propose to take any measures to remedy this situation, if so, how ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINIS TER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (c) Increase in wholesale prices almost invariably gets reflected in the retail prices but the time lag involved in this change varies depending upon the nature of the commodity. In the case of most agro-based and perishable products, which also include most of the essential commodities, increases and declines in wholesale price tend to get reflected in the retail prices with relatively little time lag. In case of most manufactured products, wholesale price cihanges take longer to get reflected in the retail prices. These differences are due to many factors, including the differential behaviour of input cost, market structures, taxes, transportation costs, inventories costs, handling and ro tailers' margins.

*(d)* Government remams vigilant in respect of price changes in wage goods and other essential commodities that affect the general public and takes steps in augmenting supply and managing demand as necessary;

**VACANT POSTS IN SBI**

2585. SHRI KAILASH NARAIN SARANG :

CHOWDHRY HARI SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the bran ches of State Bank of India, at Loni Maharajpur, Dasna and Noida under SBI Meerut Zonal Office vacancies of JMGS-I have not been filled up from amongst qualified employees for the past five years;

(b) whether it is a fact that only ad-hoc appointments by giving officiating allowance to the senior msot employees have been made to these posts during the above period ;

(c) whether this ad-hocism is likely to be ended and JMGS-I poster will be filled up on a regular basis from amongst qualified people immediately ;

(d) whether it is a fact that deposit mobilisation by the above mentioned bran ches are below the expectation due to non-filling up of those posts from amongst qualified people ; and

te) if so, by when his Ministry would fill up vacancies in the above mentioned branches ?